(d) Yes, Sir.

(e) The case is being defended and is subjudice.

Warning on stock market boom

3711. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that neither the Finance Ministry nor the RBI had given any warning signal when share transactions sky rocketed from Rs. 23,000 crores to Rs. 1,27,662 crores on April 2, 1992;

(b) whether it is also a fact that the Chief Minister of West Bengal, had warned the Finance Minister and the Government about the unusual stock market boom; and

(c) if so, what action Government had taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has been established with Statutory powers and functions to protect the interests of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market. Accordingly, SEBI had asked the Bombay Stock Exchange in March, 1992 and the other major Stock Exchanges in April, 1992 to put a ban on carry forward transactions with a view to curbing speculation in the stock market.

(b) The Chief Minister, West Bengal had sent a letter dated April, 4, 1992 to the Finance Minister drawing his attention to the boom in the stock market and requesting him to give consideration for protecting the interests of small and genuine investors.

(c) The Chief Minister, West Bengal was informed that, *inter alia* the SEBI has recently been established with statutory powers and functions for regulating the securities market and for protecting the interests of investors.

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

3712. **श्रीमती मोरा दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लाभ में 184 गुणा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) विदेशी बैंकों के संबंध में नरसिम्हम समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक केवल 20 विदेशी बैंकों ने मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप दिया है । मार्च, 1991 और 1992 को समाप्त वर्ष के लिए 20 विदेशी बैंकों का निवल लाभ क्रमशः 204.04 करोड़ रुपए और 515.37 करोड़ रुपए था । 1991 में 24 विदेशी बैंकों का कुल लाभ 233.01 करोड़ रुपए था । विदेशी बैंकों के निवल लाभ में वृद्धि का मुख्य कारण निवेशों की बिक्री में अधिक लाभ, विदेशी मुद्रा में लेनदेन और बढ़ी हुई ब्याज की प्राप्ति है ।

(ग) श्री एम० नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में विदेशी

बैंकों के लिए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

(i) विदेशी निवेश से संबंधित सरकार की नीति के अन्य पहलुओं के अनुसार विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं के रूप में या अनुषंगियों के रूप में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक इसे उपयुक्त समझता है, उन्हें अपने कार्यालय खोलने की अनुमति देने से संबंधित नीति को और अधिक उदार होना चाहिए । यह नीति समानता की सांविधिक आवश्यकताओं और ऐसे न्यूनतम समनदेशी पूंजी के रख-रखाव, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया हो, के अनुसार होगी ।

(ii) विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों के बीच संयुक्त उद्यम को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए । यह बढ़ावा विशेष रूप से व्यापार और निवेश बैंकिंग, पट्टा और वित्तीय सेवाओं के अन्य नए तरीकों में संबंधित होना चाहिए ।

(iii) विदेशी बैंकों से वही अपेक्षा की जानी चाहिए जो अपेक्षायें घरेलू बैंकों पर लागू होती हैं । यदि शाखा नेटवर्क न होने जैसी कुछ रुकावटों को देखते हुए विदेशी बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के दायित्व जैसी कुछ अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकों को होने वाली किसी भी प्रकार की संभावित प्रतिस्पर्धात्मक हानि को दूर करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए ।

(घ) से (च) भारत में विदेशी बैंकों के संबंध में समिति की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ।

Rehabilitation of sick Industries of Dhanbad

3713. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 722 given in the Rajya Sabha on 5th May, 1992 and state:

(a) what are the details of the findings and the steps taken to revive and start the companies in Dhanbad referred to the BIFR;

(b) whether operating trade unions have been associated in the process;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has reported that out of 3 companies in Dhanbad referred to them:

(i) Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) has been appointed as Operating Agency (OA) to explore the possibilities of reviving the Harry Refractory and Ceramic Works (P) Ltd. OA's report is awaited.

(ii) In the case of Bihar Firebricks Potteries Ltd., at the last hearing the Bench recorded its opinion that it is just and equitable that the sick industrial company should be wound up in terms of Section 20 of the Act. The opinion has been forwarded to the concerned High Court for further necessary action.

(iii) At the last BIFR hearing, approval was accorded to Kumardhubi Fire Clay & Silca Works to go ahead with their scheme of revival.

(b) and (c) Yes, Sir. However, although notice of the review meeting on 9-1-92 was sent to the workers' union of Harry Refractory & Ceramics Ltd., no representative was present for the meeting. The representatives of Bihar Firebricks attended the hearing on 3.7.89, though not any subsequent hearings. In the case of Kumardhubi Fire Clay Silca Works, its representatives attended both the hearings on 19.9.89 and 8.8.90;

(d) Does not arise.